

न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बर्डजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर०ए०एस० अति० सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 160/2022/अपील/एलआरएक्ट/बारा

दायरा दिनांक: 21.9.2022

अन्तर्गत धारा: 75 राज०भू राजस्व अधि०, 1956

उनवान

1. काली बाई पत्नी स्व० हरलाल
2. प्रेमचन्द आत्मज स्व० हरलाल
3. पुरुषोत्तम आत्मज स्व० हरलाल
4. रामेश्वर आत्मज स्व० हरलाल

जाति धाकड निवासीगण ग्राम आमापुरा तहसील बारा जिला बारा-राज०।

...अपीलांट्स

बनाम

1. घांसीलाल आत्मज गणेश राम जाति चमार निवासी ग्राम खण्डेला तहसील किशनगंज जिला बारा जरिये हरिराम आ० बाबूलाल ऐरवाल निवासी शिवकालोनी बारा तहसील व जिला बारा।
2. पुरुषोत्तम आ० रामकरण जाति धोबी निवासी ग्राम कलमण्डा तहसील बारा जिला बारा।
3. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारा जिला बारा।

... रेस्पोंडेन्ट्स


उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक-अपीलांट्स
श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक- रेस्पोंडेन्ट क्रम- 2

::निर्णयः::

दिनांक 27.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बारा जिला बारा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 8/2016 उनवान घांसीलाल बनाम पुरुषोत्तम आदि मे पारित निर्णय दिनांक 20.12.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध अपील राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि रेस्पोंड क्रम-1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एजआरएक्ट का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे की आराजी ख० नं० 97 रकबा 0.70 है व पुरुषोत्तम पुत्र रामकरण धोबी नि० कलमण्डा की ख० नं० 810/97 रकबा 0.71 है वाके काल आमापुरा स्थित है। ख० नं० 810/97 ख० नं० 97 से बना है। सेटलमेन्ट से पूर्व ख० नं० 97 के पुराने ख० नं० 112 है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा ख० नं० 97 नक्शा छोटा कर दिया जो पुराने ख० नं० 112 के नक्शे अनुसार नहीं है जिसे दुरुस्त कराने का वह अधिकारी है। उपखण्ड अधिकारी बारा द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम आमापुरा के ख० नं० 96 मे से 0.10 है० भूमि कम कर ख० नं० 97 मे बढ़ाई जाकर राजस्व नक्शे को दुरुस्त करने का आलौक्स जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.2021 पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने अपील न्यायालय हाजा मे व्यथित पक्षकार होना वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी बावत अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ इस आशय की पेश की गई कि ख० नं० 96 का रकबा 0.47 है० जमाबंदी मे सिवायचक अधीन नगर पालिका


अति सं. आयुक्त

बांरा (न० परिषद) है। उक्त भूमि नगर पालिका का आबादी भूमि में स्थित है इसलिये नगर पालिका बारा प्रकरण आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया है। ख० नं० 96 के उत्तर पूर्वी ओर ख० नं० 97 की 0.31 है० आराजी स्थित है जो रेस्प० क्रम-1 के खाते में दर्ज है। रेस्प० क्रम-1 ने उक्त आराजी पर आवासीय कॉलोनी अनमोल सिटी की प्लानिंग कर ख० नं० 96 की भूमि को भी अपनी प्लानिंग में सम्मिलित कर अनमोल सिटी के भूखण्डों का नक्शा जारी किया है। पूर्व में भी ख० नं० 96 की भूमि पर स्थित रास्ते को अवरूद्ध किया था जिसे नगर परिषद बांरा ने दिनांक 28.3.16 को खुलवाया था। ख० नं० 104 की 4.9600 है० एवं ख० नं० 104/674 की 0.03 है० भूमि भूमि जो कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता ख० नं० 350 से खसरा नम्बर 96 की भूमि में होकर है। अपीलांट का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। ख० नं० 96 की भूमि से रेस्प० क्रम-1 का कोई संबंध नहीं है। नक्शा संबंधी विवाद धारा 136 के अन्तर्गत निर्णित नहीं किया जा सकता इस कारण रेस्प० क्रम-1 द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कार्यवाही पोषणीय नहीं थी। गत व वर्तमान सेटलमेंट का स्केल अलग 2 है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जिससे अपीलांट व्यथित पक्षकार है तथा अपीलांट के हितों के विपरीत प्रभाव पड़ा है। अतः अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्प० क्रम-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर ख० नं० 96 की कोई भूमि रेस्प० क्रम-1 के खाते दर्ज नहीं किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

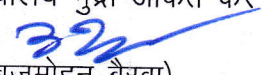
- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प० को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में रेस्प० क्रम-1 के उपस्थित नहीं होने पर तामील पूर्ण मानी जाकर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्प० क्रम-2 सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित उपर्युक्त तथ्यों को ही दोहराते हुये अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त करने तथा रेस्प० क्रम-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर ख० नं० 96 की कोई भूमि रेस्प० क्रम-1 के खाते दर्ज नहीं किये जाने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध करते हुये अपने कथन के समर्थन में डीएनजे (रेवे.)2023 पेज 1420 का न्यायिक उद्धरण पेश किया।
- 4 विद्वान अभिभाषक रेस्प० क्रम-2 ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय न्यायोचित होना जाहिर किया।
- 1 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। तथा प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर डीएनजे (रेवे.)2023 पेज 1420 पर गौर किया। अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ अपीलाधीन आदेश से व्यथित एवं हितबद्ध पक्षकार होना वर्णित करते हुये अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने व डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश की है। अतः अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी को निर्णित किया जाना न्यायोचित हैं। चूंकि जेरअपील आदेश अपीलाटस को पक्षकार बनाये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना प्रकट होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक होने से क्षम्य किया जाकर न्यायहित में अपील को अवधि मध्य माना जाता है।
- 2 हमने अपील का गुणावगुण पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन कर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर डीएनजे (रेवे.)2023 पेज 1420 का ध्यानपूर्वक गौर किया। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार

अति. सं. आयुक्त

अभिलेख तथा आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.2021 के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पों 0 क्रम-1 घांसीलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट को उपखण्ड अधिकारी बांरा द्वारा स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम आमापुरा के ख० नं० 96 में से 0.10 है० भूमि कम कर ख० नं० 97 में बढ़ाई जाकर राजस्व नक्शे को दुरुस्त करने का आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.2021 पारित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उक्त भूमि नगर पालिका की आबादी भूमि में स्थित है इसलिये नगर पालिका द्वारा प्रकरण आवश्यक पक्षकार है जिसे पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया है। ख० नं० 96 की भूमि से रेस्पों 0 क्रम-1 का कोई संबंध नहीं है। नक्शा संबंधी विवाद धारा 136 के अन्तर्गत निर्णित नहीं किया जा सकता इस कारण रेस्पों 0 क्रम-1 द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कार्यवाही पोषणीय नहीं थी। ख० नं० 104 की 4.9600 है० एवं ख० नं० 104/674 की 0.03 है० कृषि भूमि पर आने जाने का नं० 350 से खसरा नम्बर 96 की भूमि में होकर है। अपीलांट का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना जेरअपील निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है।

- 3 अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबंध में आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.021 एवं पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि आराजी ख० नं० 96 रकबा 0.4700 है० सिवायचक अधीन नगरपालिका बांरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पों 0 क्रम-1 द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर ख० नं० 96 में से 0.10 है० भूमि कम कर ख० नं० 97 में बढ़ाई जाकर राजस्व नक्शे को दुरुस्त करने का आलौच्य आदेश पारित किया है। आलौच्य आदेश नगर पालिका बांरा को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया जाना प्रकट होता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से आलौच्य जेरअपील आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि नक्शा संबंधी विवाद धारा 136 के अन्तर्गत निर्णित नहीं किया जा सकता इस कारण रेस्पों 0 क्रम-1 द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कार्यवाही पोषणीय नहीं थी क्योंकि धारा 136 एलआरएक्ट में लिपिकीय त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता है जिसको हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक प्रावधानों को अनदेखा कर आलौच्य निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। रेस्पों 0 क्रम-1 यदि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई कार्यवाही अथवा नक्शाशीट से व्यथित है तो वह सक्षम न्यायालय में राजस्व वाद अथवा अपील प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है तथा उस कार्यवाही में यह निर्णय बाधक नहीं होगा। सक्षम न्यायालय स्वतंत्र रूप से उस प्रकरण में आदेश पारित कर सकता है। उक्त तथ्यों के आलोक में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण डीएनजे (रेवे) 2023 पेज 1420 चस्पा होता है। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.21 को न्यायोचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 20.12.2021 अपास्त किया जाता है।

- 4 निर्णय आज दिनांक 27.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।


 (बृजमोहन बैरवा)
 अति० संभागीय आयुक्त
 कोटा